E content for the student of Patliputra University

Subject- Political science

Class - B. A. (Hons.) Part-III Paper VII

Topic- Role of Caste in Indian Politics

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Prof. - Pol. Sc.
R. R. S. College, Motihari.

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका काफी प्रभावकारी रही है। राजनीति में समाज का स्वरूप एवं ढाँचा का प्रकटीकरण होता है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही जातियाँ विद्यमान रही। गोत्र, वासस्थान, वैवाहिक संबंध के आधार पर यह एक मजबूत एकीकृत समूह की पहचान रहा है। अतः राजनीतिक भूमिकाओं एवं प्रक्रियाओं में जाति की अहम भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई भी राजनीतिक कर्ता अपने पीछे के जातीय समर्थन के आधार पर अपने को राजनीति में मजबूत बनाता है। इसी प्रकार जाति समूह को किसी मुद्दे से जोड़कर तथा उसके लिए आवाज उठाकर कोई भी व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्व का प्रयास कर सकता है। यह सामान्य पृष्ठभूमि यह स्पष्ट करता है कि राजनीति में जाति की प्रभावकारी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यद्यपि हर व्यवस्था में जाति का प्रभाव देखा जाता है किंतु लोकतंत्र में इसकी भूमिका और भी बढ़ जाती है। लोकतंत्र चुनाव पर आधारित व्यवस्था है। चुनावों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में समर्थकों की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीदवारों को सबसे अधिक समर्थन की उम्मीद अपनी जाति के लोगों से होती है। यही कारण है कि संपूर्ण भारत में अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में यह देखा जाता है कि निर्वाचन क्षेत्र में जातियों की संख्या किसकी ज्यादा है। निर्वाचन क्षेत्र में कुछ जातियों के संगठन के आधार पर भी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

चुनाव में प्रायः हर दल व्यापक स्तर पर जातिए समीकरण बनाकर, उसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने का प्रयास करता है कि अधिकांश जातियों का समर्थन उसे प्राप्त हो। इसी प्रकार मंत्रिमंडल के गठन, अन्य पदों पर भर्ती तथा नियुक्तियों के आधार पर विभिन्न जातियों को खुश करने का संदेश देता है। यह एक यथार्थ के रूप में भारतीय राजनीति में प्रायः सभी चुनावों में देखने को मिलता है।

भारत में जाति और राजनीति के संबंधों का विश्लेषण दो संदर्भों में करना होगा। प्रथम- जातियों का राजनीतिकरण (Politicalization of Caste) तथा राजनीति का जातीयकरण (Caste based Politics)

प्रथम दृष्टिकोण का संबंध भारतीय राजनीति की उस प्रारंभिक स्थिति से है, जिसमें उच्च प्रभुत्वशाली जातियों के लोग, अपनी संपत्ति, नौकरी, व्यवसाय तथा सामाजिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर राजनीति के कुछ अधिकर्ता हुआ करते थे। आमलोग जो सामाजिक, आर्थिक, व्यवसाय या नौकरी, पारिवारिक पृष्ठभूमि में निम्न पायदान पर हुआ करते थे, उन्हें काफी कम संख्या में राजनीति में भागीदारी मिलती थी। परिणाम स्वरूप यह महसूस किया जाने लगा कि पिछड़े सामाजिक वर्ग (जातियों) को राजनीति में सहभागी होने के लिए जागरूक किया जाय। उन्हें अपनी संख्या के बल पर प्रभावी भूमिका में लाने के लिए प्रेरित किया जाय। अर्थात जातियों का राजनीतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देकर उन्हें राजनीति में भाग लेने का अवसर दिया जाय। 1930 के दशक में बिहार में इस प्रयास के क्रम में "त्रिवेणी संघ" का निर्माण किया गया। जिसमें यादव, कुर्मी तथा कोइरी जैसी मध्य जातियों को

संचालित कर राजनीति में भागीदार तथा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देने का लक्ष्य रखा जाता था।

दूसरा दृष्टिकोण इस प्रक्रिया पर आधारित है जिसमें जातियों को एक वर्ग में उपयोग कर, उनका संगीकरण बनाकर राजनीति में सफलता प्राप्त करने का प्रयास किया जाय।

दोनों प्रक्रिया सामान्य तौर पर एक जैसा लगता है किन्तु कुछ अंतर को समझने की आवश्यकता है। पहली प्रक्रिया एक अविकसित वर्ग या समूह को राजनीति में लाने का प्रयास है। यह राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसे (Political Socialization) कहते हैं। इसमें राजनीतिक सहभागिता (Political Participation) के लिए जागरूक समाज को स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। अतः यह प्रक्रिया सकारात्मक (Positive) कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें यह नहीं कहा जाता कि केवल जाति के आधार पर ही निर्णय लिया जाय।

द्वितीय प्रक्रिया नकारात्मक है। इसमें जाति के आधार पर ही निर्णय लेने की बात की जाती है। इसमें संकीर्णता का तत्व प्रभावी है। इससे विघटन, पारस्परिक, ईर्ष्या और द्वेष की संभावना रहती है। वर्तमान भारत जातियों की राजनीति में इसी प्रकार की भूमिका से प्रभावित है।

स्वतंत्रता के बाद संविधान द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रावधान लागू कर दिया गया। इसे सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। यह लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत अच्छी बात है, किन्तु नीतियों, मुद्दों, कार्यशैली तथा नेतृत्व के संबंध में स्पष्टता के अभाव में, जातियों की भूमिका राजनीति में बढ़ती चली गई। आज स्थिति यह है कि नीति, कैडर (Cader) तथा सिद्धांतों पर आधारित

दल भी चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में समर्पित कार्यकर्ता की उपेक्षा कर जातीय समीकरणों पर आधारित उम्मीदवारों का चयन करते हैं।

नौकरीयों में आरक्षण को भी राजनीति में जातियों की भूमिका में बढ़ावा का महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है आरक्षण का लाभ लेने हेतु विभिन्न जातियाँ माँग करती हैं जिसे समर्थन कर जातियों का मत प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नौकरीयाँ चाहे जितनी कमती जाय, लेकिन आरक्षण का मुद्दा जातीय समर्थन के एक आधार के रूप में उपयोग किया जाता है।

वर्तमान समय में बहुत सी राजनीतिक पार्टियाँ जाति आधारित पार्टी के रूप में अपना स्थान बना चुकी हैं। समीकरण के तहत कुछ दूसरी जातियाँ के लोग वैसी पार्टी में होते हैं किन्तु मतदाता खास जाति के ही ज्यादा होते हैं।

वर्तमान समय में एक अच्छा (Sophisticated शब्द (Social Engeneering) का प्रयोग किया जाता है इसका सामान्य अर्थ "जातियों का समीकरण" बनाना ही है।

इस प्रकार देखते हैं कि जाति प्रभावी भूमिका में है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है लोकतंत्र के लिए इसे अच्छा नहीं माना जा सकता है किन्तु दोष जातियों में नहीं है, जबतक मुद्दों पर आधारित राजनीति लुप्त रहेगी, नेताओं के कथनी से ज्यादा करनी पर विश्वास नहीं किया जायेगा तथा नेताओं के कार्यों का मूल्यांकन अपनी जाति तथा दूसरी जाति जैसे संकीर्ण तत्वों के आधार पर अलग-अलग मानदंड होंगे, जातियों का राजनीति में दुष्प्रभाव बना रहेगा।